B.A. Part Two
Paper III rd

by :-
Dr. Shailesh Kumar
dept. of economics
raja singh college Siwan
mob- 9934788061

14.5.20

जनसंख्या
Population

क्या भारत में जनाधिक्य है ? India is over populated ?

अब भारत के संदर्भ में दो विचारों की विवेचना करनी है प्रथम यह कि भारत में जनाधिक्य है इस कथन की पुष्टि के लिए इसके समर्थक साधारणतया निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं।

(1) कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता (excessive dependence of population on agriculture) भारत की कृषि परम्परा यहाँ की मुख्य व्यवसाय है। जनसंख्या का बहुत भार है। इसके फलस्वरूप प्रति कृषक परिवार को अधिक जोत से भी कम ही भूमि मिलती है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 0.33 से घटकर आजकल लगभग 0.25 हेक्टेयर से भी कम हो गया है।

(2) खाद्यान्नों का अभाव (Shortage of foodgrains) देश की प्रायः 70% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। फिर देश की कृषि से यहाँ के निवासियों के लिए हाल तक पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। जो खाद्यान्न के अभाव को दर्शाता है और इसे दूर करने के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देश की जनसंख्या खाद्यान्न की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है। फलस्वरूप देश में जनसंख्या की वृद्धि तथा खाद्यान्न के उत्पादन में असंतुलन होने लगा किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में आयोजित प्रयत्नों के कारण कृषि के उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है। जिससे खाद्यान्न की समस्या का प्रायः स्थायी तौर पर समाधान हो गया है।

(3) उद्योग धन्धों का अविकसित होना (Lack of industrial development) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में उद्योग धन्धों के विकास पर जोर—

P.T.O

Scanned by CamScanner

आवश्यक किया जा रहा है, फिर भी देश में उतनी तीव्र गति से उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। देश में उद्योग धन्धों के पिछड़ेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 में खनिज लघु उद्योग तथा कारखानों से देश की कुल राष्ट्रीय आय का केवल 22 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ था जबकि कृषि का हिस्सा 30 प्रतिशत था। साथ ही बड़े कारखानों में उस वर्ष केवल 76 लाख व्यक्ति ही कार्य करते थे जो देश की संपूर्ण क्रियाशील जनसंख्या का एक बहुत ही छोटा भाग था।

(4) प्रतिबंधक निरोधों का अभाव (lack of preventive checks)

देश में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहाँ पर जनसंख्या के नियंत्रण में प्रतिबंधक निरोध जैसे देर से व्याह करना, आत्म संयम तथा संतति निरोध के कृत्रिम साधनों (artificial method of birth control) का प्रयोग इत्यादि काम में नहीं लाए जाते हैं। भारत में इन सारे उपायों का अभाव है। यहाँ पर शादी करना तथा बच्चा पैदा करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य समझा जाता है। इंग्लैंड तथा अमेरिका में 30 वर्ष की अविवाहित औरतें क्रमशः 41 प्रतिशत और 23 प्रतिशत है जबकि भारत में 15 वर्ष की प्रायः 75 प्रतिशत लड़कियाँ विवाहित हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में प्रजनन शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग होता है।

(5) नैसर्गिक निरोधों की प्रधानता (preponderance of positive checks)

भारत में प्रतिबंधक निरोधों का अभाव है, किन्तु यहाँ पर नैसर्गिक निरोधों की ही प्रधानता है। माल्थस के अनुसार बाढ़, अकाल, महामारी, इत्यादि नैसर्गिक निरोध जनाधिक्य की स्थिति की प्रधान सूचक है। किन्तु भारत में वर्तमान समय में भी इन प्राकृतिक आपत्तियों की प्रधानता है। प्रतिवर्ष देश में भिन्न-भिन्न भागों में बाढ़ तथा सूखा के साथ-साथ हैजा, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि महामारियों का प्रकोप भी यदाकदा पाया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप लाखों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अतएव इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान में है।

(6) निम्न जीवन स्तर (Low Standard of living) —

P.T.O.

Scanned by CamScanner

भारत में देशवासियों का निम्न जीवन स्तर भी इस बात का सबूत है कि भारत में अल्पविकास की स्थिति वर्तमान है। 1999 में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 450 डॉलर थी। जबकि उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के एक औसत निवासी की प्रति व्यक्ति आय 30600 डॉलर, जर्मनी की 25351 डॉलर तथा जापान की 32230 डॉलर थी। इससे स्पष्ट है कि एक औसत भारतवासी की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की औसत आय 80 गुना तथा जापान की सौ गुना से भी अधिक है।

7. बेकारी की समस्या (Problem of Unemployment) भारत में अल्पविकास की स्थिति का सर्वाधिक प्रमुख सूचक देश में बेकारी तथा अर्द्ध बेकारी की भीषण समस्या है। देश में लाखों व्यक्ति काम चाहते हुए भी बेकार है। आठ वर्षीय योजनाओं और विभिन्न एक वर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है देश में रोजगार दिलाने [illegible] संस्थाओं द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से यह पता चलता है कि बेकारी की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। योजनाओं के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में देश में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। चतुर्थ योजना में यह बढ़कर 120 लाख तथा आठवीं योजना में यह बढ़कर 3 करोड़ से भी अधिक हो गई। इससे स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार की सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी। और जिसके फलस्वरूप बेरोजगारों की संख्या में और भी वृद्धि हुई। और बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी अर्द्ध बेरोजगारी की स्थिति में है जो भारत में अल्पविकास अर्थव्यवस्था के सूचक हैं।